

सुशासन सप्ताह

प्रलिस के लयल:

सुशासन दवलस, सुशासन सप्ताह,, सुशासन से संबंघतल पहल, सुशासन के सद्दलधलंत ।

मेन्स के लयल:

सुशासन का महत्त्व, स्थानीय स्तर के शासन और संबंघतल चुनौतयलें में सुधार के सद्दलधलंत ।

चर्चा में क्यलें?

केंद्र सरकार 20 दसलंबर से 26 दसलंबर तक एक राष्ट्रव्यापी 'सुशासन सप्ताह' मना रही है, जसलका उद्देश्य जनता की शकलयतलें का नवलरण और नपलटान करना और ग्रामीण स्तर तक सेवा वतलरण में सुधार करना है ।

- नागरकल केंद्रतल होने के उद्देश्य से "प्रशासन गाँव की ओर" नामक अभयलान के तहत इस सप्ताह के दूरान वभलनलन कार्यक्रम आयोजतल कयल जाऐंगे ।
- 25 दसलंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बहलरी वाजपेयी की जयंती को चहलनतल करने के लयल 'सुशासन दवलस' के रूप में मनाया जाता है ।

प्रमुख बद्दल

- **परचयल:**
 - यह प्रगतशील भारत के 75 वर्षलें के उपलक्षण में 'आज़ादी का अमृत महलत्सव' समारोह के अनुरूप नागरकल-केंद्रतल शासन को बद्दावा देने और सेवा वतलरण में सुधार के लयल भारत द्वारा उटाए गए कदमलें का जशन मनाने के लयल आयोजतल कयल जाता है ।
 - इस सप्ताह के दूरान नयलोजतल करयक्रमलें की श्रृंखला का उद्देश्य केंद्र द्वारा की गई वभलनलन सुशासन पहललें को जनता के सामने लाना है ।
 - इसमें सुशासन प्रथाओं पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी शामिल होगा ।
- **वभलनलन आयोजन:**
 - जीवन की सुगमता और अनुपालन बोझ को कम करने के लयल सुधारलें का अगला चरण ।
 - सर्वोत्तम प्रथाओं पर DARPG द्वारा अनुभव साझा करने हेतु करयशाला ।
 - **मशलन करमयुगी-** आगे की राह ।
 - इस अवसर पर 'सुशासन सप्ताह पोर्टल' भी लॉन्च कयल जाऐगा तथा राजयलें और केंद्रशासतल प्रदेशलें के सभी ज़लला कलेक्ट्रलें को प्रगतल एवं उपलब्धयलें को अपलोड करने व साझा करने के लयल ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँच प्रदान की जाऐगी ।
 - ग्रामीण क्षेत्रलें में सुशासन लाने के उद्देश्य से 'प्रशासन गाँव की ओर' अभयलान शुरू कयल जाऐगा ।
- **शासन:**
 - यह नरलणय लेने तथा इन नरलणयलें के करयानवयन की एक प्रकरयल है ।
 - शासन शब्द का उपयुग कई संदर्भलें में कयल जा सकता है जैसे कल कलॉर्पोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय शासन ।
- **सुशासन के आठ लक्षण (संयुक्त राष्ट्र द्वारा वरणतल):**
 - **भागीदारी:**
 - लुगलें द्वारा सीधे या वैध मध्यवर्ती संस्थानलें के माध्यम से भागीदारी जो कल उनके हतलें का प्रतनलधतलव करतें हैं ।
 - नरलणय लेने में लुगलें को स्वतंत्र होना चाहयल ।
 - **वधलका शासन:**
 - कानूनी ढाँचा, वशलष रूप से मानव अधकलरलें से संबंघतल कानून सभी पर नषलपकष रूप से लागू होने चाहयल ।
 - **पारदर्शतल:**
 - सूचना के मुक्त प्रवाह को लेकर पारदर्शतल सुनशलचतल की जाती है ताकल प्रकरयललें, संस्थाओं और सूचनाओं तक लुगलें की सीधी पहुँच हो तथा उनहें इनको समझने व नगरलनी करने के लयल पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाती है ।

- **जवाबदेही:**
 - संस्थाओं और प्रक्रियाओं द्वारा सभी हतिधारकों को एक उचित समयसीमा के भीतर सेवा सुलभ कराने का प्रयास किया जाता है।
- **आम सहमति:**
 - सुशासन के लिये समाज में विभिन्न हतियों को लेकर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, ताकि समाज में इस पर व्यापक सहमति बिन सके किये पुरे समुदाय के सर्वोत्तम हति में है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
- **इकवटी:**
 - सभी समूहों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर प्रदान करना।
- **प्रभावशीलता और दक्षता:**
 - संसाधन और संस्थान उन परिणामों को सुनिश्चित करते हैं जो संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए जरूरतों को पूरा सकें।
- **जवाबदेही:**
 - सरकार में नरिणय लेने वाले नजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता के साथ-साथ संस्थागत हतिधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं।



■ भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएँ:

- **महिला सशक्तीकरण में कमी:**
 - सरकारी संस्थानों और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है
- **भ्रष्टाचार:**
 - भारत में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता के सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है।
 - एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन कई कारक हैं, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्तिको समय पर न्याय नहीं मिलता है। इस तरह के एक कारण के रूप में न्यायालयों में कर्मियों और संबंधित सामग्री की कमी है।
- **न्याय में देरी:**
 - एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, कति कई ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से एक सामान्य व्यक्तिको समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।
- **प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण:**
 - नचिले स्तर की सरकारें केवल तभी कुशलता से कार्य कर सकती हैं जब वे ऐसा करने हेतु सशक्त हों। यह विशेष रूप से **संचायती राज संस्थानों के लिये प्रासंगिक** है जो वर्तमान में नधियों की अपर्याप्तता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में कठनाइयों का सामना कर रही हैं।
- **राजनीतिक अपराधीकरण**
 - राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण और **राजनेताओं, सविलि सेवकों तथा व्यावसायिक घरानों के बीच साँठगाँठ** सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।
- **पर्यावरणीय सुरक्षा, सतत् विकास।**
 - वैश्वीकरण, उदारीकरण और बाज़ार अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ।

■ भारत में सुशासन के लिये पहल:

- **गुड गवर्नेंस इंडेक्स**
 - GGI को देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिये कार्मिक, लोक शकियत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
 - यह राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है।
- **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना:**
 - इसका उद्देश्य "आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये 'सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स' के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ कराना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।"
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**
 - यह शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है।
 - अन्य पहल: **नीति आयोग** की स्थापना, **मेक इन इंडिया** कार्यक्रम, **लोकपाल** आदि।

स्रोत: पीआईबी

